एस. के. अलघ

बनाम

यू. पी. राज्य और अन्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 317)

15 फरवरी, 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.

दंड संहिता, 1860 -धारा 406-आपराधिक विश्वासघात का अपराध-कंपनी के प्रबंध निदेशक/कर्मचारी का प्रत्यावर्ती दायित्व-आयोजितःआपराधिक भंग के अपराध के लिए निदेशक या अधिकारियों को प्रत्यावर्ती दायित्व नहीं दिया जाता है। कंपनी का-प्रावधान इस तरह के कानूनी कल्पना-प्रत्यावर्ती दायित्व के निर्माण पर विचार नहीं करता है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 एक फर्म का मालिक था, जो एक कंपनी का थोक विक्रेता था। उन्होंने अपीलकर्ता (कंपनी के प्रबंध निदेशक) के खिलाफ भा.दं.सं. सी. धारा 406 के तहत शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि फर्म ने डिलीवरी के लिए कंपनी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जारी किया था। कंपनी से माल, लेकिन न तो माल वितरित किया गया और न ही मसौदे वापस किए गए। कंपनी को अभियुक्त के रूप में शामिल नहीं किया गया था। अभियुक्त को तलब किया गया। इसके बाद उन्हें योग्यता के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया। पुनरीक्षण के साथ-साथ सीआर.पी.सी. धारा 482 के तहत कार्यवाही, अदालतों ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता का निर्वहन सही नहीं था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

दंड संहिता, विशेष रूप से प्रदान किए गए कुछ प्रावधानों को छोड़कर, किसी ऐसे

पक्ष की ओर से किसी भी प्रत्यावर्ती दायित्व पर विचार नहीं करती है, जिस पर अपराध करने के लिए सीधे आरोप नहीं लगाया जाता है। भा.दं.सं. सी. की खंड 406 के तहत आने वाले मामले में प्रत्यावर्ती दायित्व को निदेशकों या कंपनी के अधिकारी के लिए विस्तार योग्य नहीं माना गया है। विश्वास का आपराधिक भंग उस व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है जिसे संपत्ति सौंपी गई है। मसौदे कंपनी के नाम पर तैयार किए गए थे, भले ही अपीलकर्ता उसका प्रबंध निदेशक हो, उसे भा.दं.सं. सी. की खंड 406 के तहत अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता है। यदि और कब कोई अधिनियम विचार करता है । इस तरह की कानूनी कल्पना का निर्माण, इसलिए यह विशेष रूप से प्रदान करता है। अधिनियम के तहत निर्धारित किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में में, किसी कंपनी के निदेशक या कर्मचारी को कंपनी द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 17,18,20 और 21]

[1094-डी-ई; 1095-ए, बी, ई]}

सबिता राममूर्ति और अन्र अन्य आर. बी. एस. चन्नबसवराध्य 2006 (10) एस. सी. सी. 581; मकसूद सैयद अन्य गुजरात राज्य और अन्य। 2007 (11) स्केल 318- संदर्भित।

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयः दाण्डिक अपीलीय सं 317/ 2008

उच्च न्यायालय इलाहाबाद आपराधिक विविध आवेदन सं. 6170/2002 के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 16.04.2007 से।

आर. एफ. नरीमन, सद्भावना इंडीवर अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादीओं के लिए रत्नाकर दास और शालिनी दास, अनुव्रत शर्मा, प्रमोद स्वरूप, प्रशांत चौधरी, भरत राम और एम. सी. ढींगरा।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अवकाश अनुदत्त गई।

2. मेसर्स आकाश ट्रेडर्स आजमगढ़ के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) का एक एरिया होलसेल डीलर था, यू. पी. प्रतिवादी संख्या 2 की डीलरशिप को उक्त कंपनी द्वारा समाप्त कर दिया गया था।पहले यह सूचित किया गया था कि माल केवल उसके द्वारा जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट की प्राप्ति पर ही वितरित किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने इस तथ्य के बावजूद कि डीलरशिप को पहले समाप्त कर दिया गया था, 14.9.2000 पर माल की आपूर्ति के लिए Rs.18,000/- और. 1,50,000 की राशि के लिए दो डिमांड ड्राफ्ट भेजे।

3. उक्त मांग मसौदे कंपनी के स्थानीय बिक्री प्रभारी द्वारा से अपीलकर्ता को भेजे गए थे। यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया।

4. कंपनी द्वारा आजमगढ़ के लिए नए क्षेत्र थोक विक्रेता की नियुक्ति की गई थी।

5. शिकायतकर्ता द्वारा 24.9.2000 दिनांकित एक पत्र द्वारा सामान वितरित करने की मांग की गई थी जिसमें कहा गया था कि कंपनी पर उसका रु. 1,00,000 बकाया है। कंपनी के इस रुख को कि उसकी डीलरशिप को समाप्त कर दिया गया था, 25.9.2000 दिनांकित एक पत्र द्वारा दोहराया गया था।

6. मेसर्स आकाश ट्रेडर्स फर्म के कथित मालिक अशोक कुमार अग्रवाल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ की अदालत में अपीलकर्ता के खिलाफ खंड 406 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध करने के लिए एक शिकायत याचिका दायर की। ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इसमें अभियुक्त के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

7. 17.2.20071 पर या उसके आसपास, यानी शिकायत याचिका दायर करने के बाद, डीलर ने उक्त डिमांड ड्राफ्ट को 8.1.2002 दिनांकित करने के लिए रुपये की राशि के लिए स्वीकार कर लिया। 25.2.2001 पर या उसके आसपास, मूल शिकायतकर्ता

अशोक कुमार अग्रवाल की मृत्यु हो गई।दूसरे प्रतिवादी-आलोक कुमार अग्रवाल द्वारा 19.4.2001 पर या उसके आसपास एक प्रतिस्थापन आवेदन दायर किया गया था।

8. अन्य बातों के साथ-साथ, शिकायत याचिका में लगाए गए आरोपों पर या उनके आधार पर भरोसा करते हुए कि 'कंपनी ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से न तो सामान भेजा, न ही पैसे वापस किए'; अपीलार्थियों को बुलाने का आदेश 8.5.2001 पर पारित किया गया था।एक स्थानीय समाचार पत्र में एक लेख में इस आशय का एक प्रकाशन भी किया गया था।

9:अपीलकर्ता द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष समन के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 13.12.2001 के एक आदेश द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की खंड 245 (2) के संदर्भ में अभियुक्त को आरोपमुक्त करते हुए कहाः

> "अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि शिकायतकर्ता मेसर्स आकाश ट्रेडर्स, आजमगढ़ और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता के बीच एक समझौता हो गया। मेसर्स आकाश ट्रेडर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिकृत एजेंट थे और समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेसर्स आकाश ट्रेडर्स, आजमगढ़ को बिस्कुट की आपूर्ति करता थाः8.9.2000 पर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने समझौते के संबंध में एजेंसी को समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया। यह शिकायतकर्ता का निवेदन है कि 13.9.2001 बैंक ड्राफ्ट पर 1,68,000-ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में भेजा गया था, लेकिन आरोपी की ओर से उपरोक्त राशि 7.2.2001 तक शिकायतकर्ता को वापस नहीं की गई। अभियुक्त की ओर से दलील दी गई है कि

रुपये का बैंक ड्राफ्ट-1,68,000-मेसर्स आकाश ट्रेडर्स को वापस कर दिया गया था। 8.1.2001 और इसका भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा 19.2.2001 पर विरोध में प्राप्त किया गया था।उपरोक्त संदर्भ के संबंध में मामले का निर्णय होने के बाद दोनों मुकदमों को यह कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि यदि किसी मामले में दीवानी या आपराधिक मामला बनाया जाता है तो दीवानी राहत प्राप्त करने के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, यह तय करना होगा कि क्या व्यावसायिक लेन-देन के दौरान दोनों पक्षों के बीच प्रथमदृष्टया आपराधिक मामला पाया गया था? यदि वर्तमान मामले में कोई आपराधिक मामला नहीं पाया जाता है तो खंड 245 (2) सीआर.पी.सी. के तहत किसी भी स्तर पर जारी किया गया। अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच 13.9.2001 बैंक ड्राफ्ट पर एजेंसी के संबंध में समझौते की समाप्ति के बाद रु. 1,68,000-बिस्कुट की आपूर्ति के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा गया था। इससे पहले भी मेसर्स आकाश ट्रेडर्स आजमगढ़ के पक्ष में एजेंसी के संबंध में दिनांकित 8.9.2000 समझौता पहले ही समाप्त कर दिया गया है।शिकायतकर्ता ने रुपये की राशि वापस प्राप्त करने के लिए-दिनांकित 11.10.2000 और 21.10.2000 पत्र भेजे लेकिन 7.2.2001 तक, शिकायतकर्ता को रुपये की उपरोक्त राशि वापस नहीं मिली। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक, केशवपुरम, दिल्ली के बैंक ड्राफ्ट की फाइल के साथ संलग्न पत्र की फोटो प्रति के अवलोकन से।यह बन गया है स्पष्ट करें कि मेसर्स आकाश ट्रेडर्स, आजमगढ़ के पक्ष में और उसके बाद रुपये की राशि के लिए बैंक ड्राफ्ट सं . 597805 दिनांकित 8.1.2001 पहले ही तैयार किया जा चुका था।

19.2.2001 पर मंजूरी की विभागीय कार्यवाही शिकायतकर्ता को 19.2.2001 पर राशि वापस मिल गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त ने शिकायतकर्ता मेसर्स आकाश ट्रेडर्स के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा से रुपये की राशि हस्तांतरित की थी, इस प्रकार, लेनदेन में बैंक ड्राफ्ट की राशि को वापस करने में जो भी देरी की गई थी। बैंकिंग प्रक्रिया के कारण किए जा रहे भुगतान से संबंधित कार्यवाही और उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां आवेदक/अभियुक्त की ओर से आपराधिक गबन का कोई इरादा नहीं था और इस प्रकार, अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने का कोई उचित आधार नहीं है।

इसलिए, खंड 245 (2) सीआर.पी.सी. के तहत मामले की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है और आरोपी को रिहा कर दिया जाता है।"

11. शिकायतकर्ता द्वारा इसके खिलाफ एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था, जिसे 5.6.2002 दिनांकित आदेश के कारण अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया थाः

"फाइल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 13.12.2001 के विवादित आदेश में खंड 244 सीआर.पी.सी. के प्रावधानों के तहत विस्तार से साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है. लेकिन खंड 244 सीआर.पी.सी. के तहत शिकायतकर्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं देकर. खंड 245 (2) सीआर.पी.सी. के प्रावधानों के तहत विवादित आदेश पारित किया है. जो कानूनी और उचित नहीं है। खंड 244 सीआर.पी.सी..the के प्रावधानों के तहत शिकायतकर्ता को कानून के

अनुसार विस्तार से साक्ष्य दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए।उपरोक्त प्रावधानों के तहत, सबूतों को रिकॉर्ड में लिए जाने के बाद आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं, अन्यथा खंड 245-सीआर.पी.सी. के तहत आदेश पारित करना उचित और न्यायोचित होगा।"

12. दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया थाः

"आवेदकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अवलोकन और विवादित आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक के खिलाफ प्रथमदृष्टया अपराध किया गया है और संज्ञान लेने और आवेदकों को बुलाने में कोई प्रक्रियात्मक गलती नहीं है, इसलिए, विद्वान मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा पारित दिनांक 8.5.2001 और विद्वान अतिरिक्त सत्रों द्वारा पारित 5.6.2002 के विवादित आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना।

फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2, आजमगढ़ के न्यायाधीश को अस्वीकार कर दिया जाता है।

3.7.2002 दिनांकित अंतरिम रोक स्थगन आदेश को खाली कर दिया गया है।

तदनुसार, यह आवेदन खारिज कर दिया जाता है।"

13. विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या शिकायत याचिका, भले ही अंकित मूल्य दी गई हो और पूरी तरह से सही मानी गई हो, भारतीय दंड संहिता की खंड 406 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का

खुलासा करती है।

14. खंड 405 'आपराधिक भंग' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ हैः

खंड 405— विश्वास का आपराधिक भंग-जो कोई भी, किसी भी तरह से संपत्ति के साथ सौंपा गया है, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है, या बेईमानी से उपयोग करता है या उस संपत्ति का निपटान करता है कानून के किसी भी निर्देश का भंग करते हुए जिसमें उस तरीके को निर्धारित किया गया है जिसमें इस तरह के ट्रस्ट का निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध का, जिसे उसने ऐसे ट्रस्ट के निर्वहन को छूते हुए व्यक्त या निहित किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित किया है, वह "विश्वास का आपराधिक भंग" करता है"

15. अपीलकर्ता नं. 1 कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। उत्तरदाता संख्या 3 इसके महाप्रबंधक थे। निर्विवाद रूप से, कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है। मांग मसौदे कंपनी के नाम पर जारी किए गए थे। कंपनी को आरोपी नहीं बनाया गया था। डीलरशिप समझौता मेसर्स आकाश ट्रेडर्स और कंपनी के बीच हुआ था।

16. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद स्वरूप ने प्रस्तुत किया कि प्रथमदृष्टया, अपीलकर्ता कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी था और नियंत्रण में था, इसलिए उसे कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

17. भारतीय दंड संहिता, विशेष रूप से इसके लिए प्रदान किए गए कुछ प्रावधानों को छोड़कर, उस पक्ष की ओर से किसी भी प्रत्यावर्ती दायित्व पर विचार नहीं करती है, जिस पर सीधे किसी अपराध के लिए आरोप नहीं लगाया गया है।

18. विश्वास का घोर भंग उस व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है जिसे संपत्ति

सौंपी गई है।

19. खंड 406 के तहत अपराध के तत्व इस प्रकार हैंः

"(1) एक व्यक्ति को संपत्ति सौंपी जानी चाहिए थी, या संपत्ति पर प्रभुत्व सौंपा जाना चाहिए था;

(2) उस व्यक्ति को बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करना चाहिए या उस संपत्ति को अपने उपयोग में बदलना चाहिए, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या निपटान करना चाहिए या जानबूझकर कोई नुकसान उठाना चाहिए।

ऐसा करने के लिए अन्य व्यक्ति;

(3) कि इस तरह का दुरुपयोग, रूपांतरण, उपयोग या निपटान उस विधि को निर्धारित करने वाले कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन होना चाहिए जिसमें ऐसा न्यास होना है।

ऐसे न्यास के निर्वहन को छूते हुए, व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कानूनी अनुबंध का निर्वहन या निष्पादन।"

20. चूंकि, स्वीकार्य रूप से, कंपनी के नाम पर मसौदे तैयार किए गए थे, भले ही अपीलकर्ता इसका प्रबंध निदेशक हो, उसे भारतीय दंड संहिता की खंड 406 के तहत अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता है।यदि और कब कोई अधिनियम निर्माण पर विचार करता है इस तरह की कानूनी कल्पना के बारे में, यह विशेष रूप से इसके लिए प्रदान करता है।अधिनियम के तहत निर्धारित किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में में, किसी कंपनी के निदेशक या कर्मचारी को कंपनी द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।{सबिता राममूर्ति और अन्र.

बनाम आर. बी. एस. चन्नबसवराध्य [(2006) 10 एससीसी 581} देखें।

21. हम इस संबंध में ध्यान दे सकते हैं कि आवश्यक प्रतिभूति अधिनियम, परक्राम्य लिखत अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952 आदि के प्रावधानों ने इस तरह के प्रत्यावर्ती दायित्व का निर्माण किया है।यह ध्यान दें दिलचस्प है कि 1952 के अधिनियम की खंड 14ए विशेष रूप से कंपनी द्वारा कर्मचारियों से कटौती की गई राशि के संबंध में आपराधिक भंग का अपराध पैदा करती है।भारतीय दंड संहिता की खंड 405 से जुड़े स्पष्टीकरणों के संदर्भ में, इस प्रभाव के लिए एक कानूनी कल्पना बनाई गई है कि नियोक्ता को आपराधिक भंग का अपराध किया हुआ माना जाएगा। जबकि कंपनी के मामलों के प्रभारी और उसके नियंत्रण वाले व्यक्ति को कंपनी के साथ कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की खंड 406 के तहत आने वाले मामले में भी प्रत्यावर्ती दायित्व को कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों के लिए विस्तार योग्य नहीं माना गया है। {मकसूद सैय्यद अन्य गुजरात राज्य और अन्य देखें। [2007 (11) स्केल 318]]।

22. इसलिए, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की।

23. उपरोक्त कारणों से, विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।इसे तदनुसार अलग रखा जाता है। अपील की अनुमति है। प्रत्यर्थी सं. 2 अपीलकर्ता को परेशान करने के लिए उसकी लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी है जिसकी राशि रु. 1,00,000-(केवल एक लाख रुपये) निर्धारित की गई है।

के. के. टी. अपील को अनुमति दी गई।